ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर तीन क्षेत्रीय विकास क्लस्टर प्रस्तावित

विश्व बैंक तैयार करेगा तीनों क्षेत्रों की संरचना योजना

लखनऊ, 18 सितम्बर 2013

विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर (ईडीएफसी) के संरेखण पर प्रस्तावित तीन क्षेत्रीय विकास क्लस्टरों की संरचना योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। ये तीन क्षेत्र हैं– **औरैया–कन्नौज–कानपुर** (कानपुर देहात), **इलाहाबाद–वाराणसी** (कौशाम्बी एवं संत रविदास नगर), **आगरा–अलीगढ़** (मथुरा, हाथरस एवं फिरोज़ाबाद)।

इस संबंध में निर्णय आज यहाँ विश्व बैंक के लीड अर्बन स्पेशियलिस्ट *बरजोर मेहता* द्वारा 'उत्तर प्रदेश में सामरिक क्षेत्रीय विकास के विकल्प' (Strategic Regional Development Options for Uttar Pradesh) की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) –डॉ. सूर्य प्रताप सिंह के समक्ष प्रस्तुतिकरण के पश्चात् लिया गया। यह भी तय किया गया कि संरचना योजना को तैयार करने हेतु नियम व शर्तों को एक माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्षेत्रों की गहन विश्लेषणात्मक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को इस परियोजना पर कार्य करने में विश्व बैंक की टीम के साथ सहयोग के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया।

विश्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय विकास क्लस्टरों के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) –डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा– "क्योंकि उत्तर प्रदेश ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर से अधिकतम लाभान्वित हो रहा है, अतः इसके प्रभाव–क्षेत्र की संरचना योजना तथा अवस्थापना विकास व्यवस्थित ढंग से किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में अनियोजित विकास के कारण बाधाएं न उत्पन्न हों।" उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि यहाँ विशाल उपभोक्ता आधार, सुलभ कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधनों तथा इस प्रयोजन हेतु भूमि की प्रचुरता के कारण उद्योगों एवं विनिर्माण की असीम सम्भावनाएं मौजूद हैं।**

यह सूचित करते हुए कि ईडीएफसी विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से विकसित किया जाएगा, **विश्व बैंक के लीड अर्बन स्पेशियलिस्ट *बरजोर मेहता* ने बताया–"विकास के लिए औरैया–कानपुर, इलाहाबाद–वाराणसी, आगरा–अलीगढ़ क्षेत्रों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि बाजार तक पहुँच, आर्थिक गतिविधियों, प्रति–व्यक्ति औद्योगिक निवेश, शिक्षा का स्तर, व्यापारिक केन्द्रों की प्रगति आदि मापदण्डों पर ये क्षेत्र पहले से ही सक्रिय हैं इसलिए इनका विकास करने में लागत भी कम आएगी और विकास की गति भी तेज होगी।" मेहता ने कहा कि नोड के स्थान पर क्लस्टरों का विकास इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि क्लस्टर विकास से अधिक बड़े क्षेत्र को लाभ होगा।**

बाद में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमण्डल ने **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), आलोक रंजन से भेंट की** और राज्य के दौरे का उद्येश्य बताया। **आईआईडीसी, आलोक रंजन ने कहा कि ईडीएफसी परियोजना राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगी अतः राज्य सरकार इस परियोजना के विकास हेतु प्रोएक्टिव है।**

लीड अर्बन स्पेशियलिस्ट बरजोर मेहता के अलावा विश्व बैंक की इस नौ सदस्यी टीम के सदस्य जो राज्य का दौरा कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं– कन्सल्टिंग इकोनॉमिस्ट एण्ड प्लानर–*प्रोफेसर डेविड डॉवल;* सीनियर कन्ट्री इकोनॉमिस्ट, विश्व बैंक–*डेनिस मेद्वेदेव;* विश्व बैंक की दक्षिण ऐशिया की अर्बन डेवलपमेंट इकाई के लीड इकोनॉमिस्ट–*पीटर एलिस;* लीड अर्बन इकोनॉमिस्ट–*सोंगसू चोई;* अर्बन स्पेशियलिस्ट–*जोन खेर कॉ, सांगयून चियोन, विभू जैन तथा पारूल अग्रवाल।* ईडीएफसी के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के लीड अर्बन स्पेशियलिस्ट बरजोर मेहता को विकल्प प्रपत्र (Option Paper) तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष जुलाई में विश्व बैंक के दल ने प्रदेश में दो क्षेत्रों, औरैया एवं इलाहाबाद की योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी। किन्तु अब विश्व बैंक प्रस्तावित तीनों क्षेत्रों की संरचना योजना तैयार करेगा।

ज्ञात हो कि ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर परियोजना की कुल लम्बाई 1840 किमी जो पंजाब से प्रारम्भ होकर मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल होकर गुजरेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि इसका लगभग 57 प्रतिशत 1049 किमी लम्बा भाग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। राज्य सरकार ने वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर पर दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की तर्ज पर ईडीएफसी पर अमृतसर–दिल्ली–कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने हेतु कॉन्सेप्ट पेपर भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया है।

———————————————